(c) if not, whether Government propose to take any action in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKISHAN MALAVIYA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A working group has been set up to work out a fresh set of criteria for a new Centrally sponsored Scheme for increasing the strength and mobility of the employment machinery.

Demand and Production of Sugar in Orissa

1206. KUMARI SUSHILA TIRIA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the annual demand of sugar in Orissa during 7th Five year plan period, year-wise;

(b) what is the annual production of sugar in that State; and

(c) the quantity of sugar exported so far during the 7th Five Year Plan period?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) Under the present policy of partial control, the monthly levy sugar quota is allotted to States/Union Territories on the basis of uniform norms and not as per demand/request. The monthly levy sugar quota of Orissa, is 12393 tonnes from February, 1987 onwards based on 425 grams per capita monthly availability for projected population as on 1.10.1986. As regards free sale sugar, there are no movement restrictions from factories to licensed whole-sale sugar dealers in any State.

(b) Annual production of sugar by the factories in Orissa during the 7th plan period is as under:

Sugar Year	Quantity in tonnes
(October-September)	13396
1985-86	21361
1986-87	. 27816
1987-88	9325
1988-89 (7.2.89)	

(c) The quantity of sugar exported during the 7th plan period is as under:-

Financial Year	Quantity in lakh tonnes
1985-86	0.41
1986-87	0.34
1987-88	0.22
1988-89	0.32(p)

(p)= Provisional

बिहार में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की विफलता

1207. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:
श्री राम जेठमलानी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 नवम्बर, 1988 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "आई०आर०डी०पी० फेल्स टू बेनिफिट ट्राइ-बल्स इन बिहार" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) उस पर अब तक जो कार्यवाही की गई है, उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) जेवियर इन्सटीट्यूट आफ सोशल सर्विस ने नवम्बर, 1988 में "रूरल डेवेल्पमेंट नीड्स ए प्रोफेशनल एप्रोच" पर एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सेमिनार में एक पेपर "आई०आर०डी०पी० एण्ड दि टाइबल पुअर" के बारे में था। यह पेपर बिहार में 5 आदिवासी बाहुल्य वाले जिलों की 77 पारिवारिक अनुसूचियों पर आधारित है जिन्हें ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए समवर्ती मूल्यांकन अध्ययनों के लिए भरा गया था।

(ग) इस पेपर के मुख्य निष्कर्ष ये हैं कि सहायता प्राप्त 77 लाभार्थियों में से हांलाकि कोई भी लाभार्थी गरीबी की संशोधित 6400 रुपये की रेखा को पार नहीं कर सका, परन्तु कार्यक्रम के अंतर्गत सुलभ की गई परिसम्पत्तियों में से 31 लाभार्थियों की बढ़ती हुई आय प्राप्त हुई। अधिकांश मामलों में कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए गतिविधि का चयन सही नहीं था। पशुओं की मृत्यु आमतौर पर ऋणग्रस्तता का कारण थी। इसके अलावा, ऋणों की वापिसी-अदायगी करने में अधिकांश दोषी व्यक्तियों ने उपभोज्य प्रयोजन हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई सहायता का उपयोग कर लिया था।

(घ) राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति अधिक निवेश, आर्थिक गतिविधियों का सही चयन अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, बैंकों को भी इस संबंध में सलाह दी गई है।

मुख्य समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग ने भी बिहार सहित सभी राज्य सरकारों को उपचारी कार्रवाई करने हेतु लिखा है।

Supersession of National level Federation like NCCF

1208. SHRI SHANKER SINH VAGHELA:SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether under the Multistate-Coop-Societies Act, 1984 Government are empowered to keep a National Level Federation under Supersession for a max imum period of two years;

(b) if so, whether this time limit in case of NCCF is to expire by mid October, 1989;

(c) whether Government is hopeful of achieving its object of superseding the NCCF by that date ;

(d) what are the achievements made by Government in improving the functioning of the NCCF, so far; and

(e) how many administrators and Managing Directors have been changed since the date of take over by Government on 16th October 1987 and what were the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) Yes, sir.

(b) The period of present supersession is upto 14.4.1989.

(c) and (d) A number of remedial measures have been taken to improve the functioning of the NCCF.

(e) There was one change in the in-cumbancy of administrator due to'his superannuation from service. Similarly there was one change in the post of regular Managing Director because of his transfer to other Department. However, in between certain adhoc arrangements had to be made.